[2023] 3 एस.सी.आर. 165

इम्तियाज अहमद मल्ला

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 678/2021)

28 फरवरी, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, जे.जे.]

सर्विस कानून: बहाली - याचिकाकर्ता को जम्मू और कश्मीर एग्जीक्यूटिव पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया - उसने आपराधिक केस में अपनी संलिप्तता के बारे में जानकारी छिपाई - इसके मद्देनजर, उसका अपॉइंटमेंट आदेश कैंसल कर दिया गया - बाद में, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ पेंडिंग आपराधिक केस में बरी कर दिया गया - हाई कोर्ट ने कैंसलेशन आदेश को रद्द कर दिया - उत्तरदाता को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया - पुनर्विचार पर, पुलिस डायरेक्टर जनरल ने याचिकाकर्ता के आपराधिक बैकग्राउंड को देखते हुए, उसे पद के लिए अनफिट पाया - याचिकाकर्ता ने बहाली के लिए रिट याचिका दायर की - हालांकि, सिंगल बेंच के साथ-साथ डिवीजन बेंच ने भी पुलिस डायरेक्टर जनरल के फैसले को बरकरार रखा - अपील पर, माना: सिर्फ आपराधिक केस में बरी होने से कोई कर्मचारी सर्विस में बहाली का हकदार नहीं हो जाता - पुलिस फोर्स में ईमानदारी और ऊंचे आचरण की ज़रूरत होती है - नीचे की कोर्ट ने सही माना कि पुलिस हायरार्की में सबसे बड़ा अधिकारी होने के नाते, डायरेक्टर जनरल ही पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए सबसे सही जज थे - इस तरह, कोई गैर-कानूनी नहीं हुआ और आरोपित आदेश में कोई दुर्बलता न्यायोचित और उचित है - अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है - भारत का संविधान - अनुच्छेद 136 - रणबीर दंड संहिता - धारा 379 - वन अधिनियम - धारा 6 ।

भारत का संविधान: अनुच्छेद 136 - के तहत विशेष और असाधारण शक्ति - का दायरा - माना गया: दुर्लभ और असाधारण मामलों में प्रयोग किया जाएगा।

शब्द और वाक्यांश: "सम्माननीय बरी" - अर्थ।

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और अन्य **(2018) 1 एस.सी.सी 797: [2018] 1 एस.सी.आर 112;** पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य बनाम मेहर सिंह **(2013) 7 एस.सी.सी 685: [2013]**

13 एस.सी.आर 432; भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन, नई दिल्ली बनाम भोपाल सिंह पांचाल **(1994) 1 एस.सी.सी 541: [1993] 3 अनुपूरक एस.सी.आर 586;** आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ और अन्य **ए.आई.आर 1964 एस.सी 787: [1964] एस.सी.आर 431;** अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **(2016) 8 एस.सी.सी 471: [2016] 7 एस.सी.आर 445** - को संदर्भित किया गया।

केस लॉ संदर्भ

[2018] 1 एस.सी.आर 112	**संदर्भित**	**पैरा 4**
[2018] 1 एस.सी.आर 112	**संदर्भित**	**पैरा 9**
[2018] 1 एस.सी.आर 112	**संदर्भित**	**पैरा 11**
[2018] 1 एस.सी.आर 112	**संदर्भित**	**पैरा 11**
[2018] 1 एस.सी.आर 112	**संदर्भित**	**पैरा 13**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 678/2021।

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर के दिनांक 09.08.2019 के निर्णय और आदेश से, एल.पी.ए.एस.डब्लू. संख्या 71/2018 में।

याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण विक्रम हेगड़े, चितवन शर्मा।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण शैलेश मडियाल, पार्थ अवस्थी, वैभव सभरवाल, अक्षय कुमार

कोर्ट का फैसला सुनाया गया

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. यह स्पेशल लीव याचिका जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट, श्रीनगर के एल.पी.ए.एस.डब्लू. संख्या 71/2018 में 09.08.2019 के जजमेंट और आदेश के खिलाफ है, जिसके तहत हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता करने वाले की अपील खारिज कर दी थी और सिंगल बेंच के 14.05.2018 के आदेश को पुष्टि किया था, जिसमें एस.डब्ल्यू.पी संख्या 1766/2017. को खारिज किया गया था।
2. आसान शब्दों में कहें तो, याचिकाकर्ता ने 2008-2009 में जम्मू और कश्मीर एग्जीक्यूटिव पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए हुए सिलेक्शन प्रोसेस में कामयाबी से हिस्सा लिया था, और उसे 20.08.2009 का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को नौ महीने का बी.आर.टी.सी. कोर्स करने के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, मणिगाम में भेजा गया। ऐसा लगता है कि इसके बाद याचिकाकर्ता समेत दस नए भर्ती हुए कांस्टेबलों की सर्च स्लिप, रिकॉर्ड और रेफरेंस के लिए डायरेक्टर, फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सी.पी.पी.बी) और एन.सी.आर.बी. ईस्ट, नई दिल्ली को भेजी गईं, और उस ब्यूरो ने 07.12.2009 के लेटर के ज़रिए जवाब दिया कि याचिकाकर्ता रणबीर पीनल कोड (आर.पी.सी.) के सेक्शन 379 और

फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन 6 के तहत क्रालगुंड पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. नंबर 52/2007 के तौर पर रजिस्टर्ड एक केस में शामिल था। बताया गया कि वह केस चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, हंदवाड़ा के सामने पेंडिंग था। पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हंदवाड़ा ने याचिकाकर्ता का सिलेक्शन कैंसिल करने के लिए यह मामला डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, एन.के.आर., बारामूला के सामने उठाया। जांच के दौरान, याचिकाकर्ता को आरोपों की समरी और चार्जशीट दी गई। यह आरोप लगाया गया कि उस आपराधिक केस में, याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के चार दिन बाद बेल पर रिहा कर दिया गया था, और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक केस में अपने शामिल होने की अच्छी जानकारी थी और उसने जानबूझकर वह जानकारी छिपाई थी। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता ने पुलिस वेरिफिकेशन के समय क्लीन चिट पाने के लिए अपना घर पखरीबल के बजाय गुंडचोबोत्रा गांव में दिखाया था। इन हालात में, याचिकाकर्ता का 20.08.2009 का अपॉइंटमेंट आदेश 01.03.2010 के आदेश से कैंसिल कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता ने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के उस आदेश को हाई कोर्ट में एस.डब्ल्यू.पी. नंबर 2616/2011 नाम से रिट याचिका फाइल करके चैलेंज किया। इस बीच, याचिकाकर्ता पर आपराधिक केस में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, हंदवाड़ा की कोर्ट ने 26.04.2011 के जजमेंट के ज़रिए ट्रायल किया और उसे बरी कर दिया। इसलिए, उस याचिका का निपटारा 18.05.2016 के आदेश के ज़रिए किया गया, जिसके तहत हाई कोर्ट ने 01.03.2010 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया। संबंधित उत्तरदाता को 27.02.2012 के कम्युनिकेशन को देखते हुए आगे एक्शन लेने का निर्देश दिया गया, जो याचिकाकर्ता जैसी ही स्थिति वाले दूसरे लोगों के बारे में था। दोबारा विचार करने पर, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के पुलिस डायरेक्टर जनरल ने 31.07.2017 को आदेश पास किया, जिसमें दूसरी बातों के साथ यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के आपराधिक बैकग्राउंड को देखते हुए, उसे डिसिप्लिन्ड फोर्स में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सही नहीं पाया गया।

4. 31.07.2017 के उस आदेश से नाराज़ होकर, याचिकाकर्ता ने एस.डब्ल्यू.पी. नंबर 1766/2017 के तहत रिट याचिका फाइल की, जिसमें नतीजों के फ़ायदों के साथ बहाली की मांग की गई थी। उस रिट याचिका को सिंगल बेंच ने 14.05.2018 के फ़ैसले और आदेश से खारिज कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच ने यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़

प्रशासन एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार एवं अन्य[1] के फ़ैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के पदानुक्रम में सबसे ऊंचे ओहदे वाले पुलिस डायरेक्टर जनरल के उस फ़ैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता जिसमें अपील करने वाले को पुलिस फ़ोर्स में शामिल करने की काबिलियत पर विचार किया गया था। इसलिए, नाराज़ याचिकाकर्ता ने एल.पी.ए. फाइल की, जिसे डिवीज़न बेंच ने उस आदेश से खारिज कर दिया।

5. हालांकि दोनों पार्टियों के वकीलों ने इस मामले पर लंबी बहस की, लेकिन इस कोर्ट के सामने जो सवाल है, वह यह है कि क्या जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के पुलिस डायरेक्टर जनरल, जो याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि याचिकाकर्ता अपने आपराधिक बैकग्राउंड को देखते हुए पुलिस फोर्स में पोस्ट के लिए फिट नहीं है, आपराधिक केस में बरी होने पर याचिकाकर्ता को फिर से नौकरी पर रखने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह बताने की कोशिश की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रहे आपराधिक ट्रायल में, प्रॉसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछताछ करने में फेल रहा और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में भी फेल रहा, और इसलिए उस केस में उसके बरी होने को इज्ज़तदार बरी माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का आपराधिक बैकग्राउंड था, यह मानने का आधार ही रेस्पोंडेंट्स के पास नहीं रहा, क्योंकि उसे सही आपराधिक कोर्ट ने बरी कर दिया था।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की इस बात को समझने के लिए, हंदवाड़ा के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के 26.04.2011 के फैसले का ज़रूरी हिस्सा दोबारा पेश करना सही होगा, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था।

> "आई.ओ. को पेश नहीं किया गया और उसकी जांच नहीं की गई, जो प्रॉसिक्यूशन केस में कानूनी तौर पर कमज़ोरी है क्योंकि ज़रूरी विरोधाभासों का जवाब नहीं दिया गया है और न ही साइट प्लान साबित किया गया है। इसके अलावा, लकड़ी ज़ब्त करना गवाहों द्वारा साबित नहीं किया गया है। किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया है कि आरोपियों ने जंगल में चोरी की थी और विलो के पेड़ आरोपियों के कब्ज़े में पाए गए थे। विरोधाभासी सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि संदेह का लाभ आरोपियों को जाता है। प्रॉसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ़ सेक्शन 379 आर.पी.सी., 6 वन अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इसलिए, प्रॉसिक्यूशन का केस फेल हो जाता है। चालान खारिज किया जाता है।

[1] (2018) 1 एस.सी.सी 797

आरोपियों को सेक्शन 379 आर.पी.सी. 6 वन अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपों से बरी किया जाता है। आरोपी ज़मानत पर हैं। उनके ज़मानत बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड खारिज किए जाते हैं। चूंकि ज़ब्त करने की कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू की थी, इसलिए लकड़ी का निपटारा कर दिया गया है। चालान को सही तरीके से पूरा होने के बाद रिकॉर्ड में भेज दिया जाए।"

8. इस बात के अलावा कि आपराधिक प्रोसीजर कोड में कहीं भी "ऑनरेबल एक्विटटल" शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, जैसा कि उस आपराधिक केस में पास किए गए पहले बताए गए आदेश से पता चलता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता पर केस चला था, रिकॉर्ड में आए उलटे सबूतों को देखते हुए याचिकाकर्ता को डाउट का बेनिफिट दिया गया था, और प्रॉसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछताछ भी नहीं की थी।

9. **कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, नई दिल्ली और अन्य बनाम मेहर सिंह**[2] के मामले में, इस कोर्ट ने मौजूदा मामले से जुड़े मिलते-जुलते मुद्दों पर नीचे दिया है:

> **"25.** इस न्यायालय ने एस. समुथिराम [पुलिस महानिरीक्षक बनाम एस. समुथिराम, (2013) 1 एस.सी.सी 598: (2013) 1 एस.सी.सी (क्रि) 566: (2013) 1 एस.सी.सी (एल एंड एस) 229] में अभिव्यक्ति "सम्मानजनक बरी" पर विचार किया था। उस मामले में यह न्यायालय एक ऐसी स्थिति से चिंतित था जहां एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। उनके खिलाफ धारा 509 आईपीसी और ईव-टीजिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आपराधिक मामला लंबित था। प्रमुख गवाहों की जांच न होने के कारण उन्हें उस मामले में बरी कर दिया गया था। आपराधिक मामले के संचालन में एक गंभीर दोष था। दो महत्वपूर्ण गवाह मुकर गए। आर.बी.आई बनाम भोपाल सिंह पांचाल [(1994) 1 एस.सी.सी 541: (1994) 26 ए.टी.सी 619], जहां कुछ इसी तरह की तथ्य स्थिति में, इस न्यायालय ने एक कर्मचारी को इस आधार पर सेवा में बहाल करने से इनकार करने के बैंक की कार्रवाई को सही ठहराया कि आपराधिक मामले में उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था और इसलिए यह एक सम्मानजनक बरी नहीं था, इस न्यायालय ने माना कि विभागीय कार्यवाही में लगाए गए दंड को रद्द करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था। इस न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति "सम्मानजनक बरी", "दोष से बरी" और "पूरी तरह से दोषमुक्त" आपराधिक प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं। उन्हें न्यायिक घोषणाओं

[2] (2013) 7 एस.सी.सी 685

द्वारा गढ़ा गया है। यह परिभाषित करना मुश्किल है कि "सम्मानजनक रूप से बरी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। इस न्यायालय ने व्यक्त किया कि जब अभियोजन पक्ष के मामले पर पूर्ण विचार-विमर्श के बाद अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहता है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया गया था।

26. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि क्योंकि डिपार्टमेंटल कार्रवाई का मकसद ऐसे लोगों को, जो गंभीर गलत काम या ड्यूटी में लापरवाही के दोषी हैं या जो नैतिक पतन के गंभीर मामलों में दोषी हैं, अगर ज़रूरी हो तो डिपार्टमेंट से बाहर रखना है, क्योंकि वे डिपार्टमेंट को खराब करते हैं, तो निश्चित रूप से ऊपर बताए गए सिद्धांत पुलिस डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति की एंट्री के समय यानी भर्ती के समय ज़्यादा सख्ती से लागू होंगे। अगर स्क्रीनिंग कमेटी को पता चलता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ नैतिक पतन से जुड़ा गंभीर मामला दर्ज है, उसे टेक्निकल आधार पर बरी कर दिया गया है या उसी आरोप से बरी कर दिया गया है, लेकिन बरी होना सम्मानजनक नहीं है, तो स्क्रीनिंग कमेटी को उसकी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार होगा। डिसिप्लिनरी फोर्स में लोगों को नियुक्त करते समय और कड़े नियम लागू करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है।"

10. इसमें आगे कहा गया कि यदि स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला गलत इरादे से या बाहरी कारणों से नहीं लिया गया है, तो उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

35. पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है। समाज में लॉ एंड आदेश और पब्लिक आदेश बनाए रखने की बड़ी ज़िम्मेदारी इस पर होती है। लोग इस पर बहुत भरोसा और विश्वास करते हैं। इसे उस भरोसे के लायक होना चाहिए। पुलिस फोर्स में शामिल होने की इच्छा रखने वाला कैंडिडेट बहुत ईमानदार होना चाहिए। उसका कैरेक्टर और ईमानदारी बेदाग होनी चाहिए। आपराधिक बैकग्राउंड वाला व्यक्ति इस कैटेगरी में फिट नहीं होगा। भले ही उसे आपराधिक केस में बरी या डिस्चार्ज कर दिया गया हो, उस बरी या डिस्चार्ज आदेश की जांच करनी होगी कि क्या उसे केस में पूरी तरह से बरी किया गया है, क्योंकि उसके क्राइम करने की संभावना भी पुलिस फोर्स के डिसिप्लिन के लिए खतरा पैदा करती है। इसलिए, स्टैंडिंग आदेश ने इन मामलों में फैसले लेने का काम स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा है।

स्क्रीनिंग कमेटी का फ़ैसला आख़िरी माना जाना चाहिए, जब तक कि वह गलत इरादे से न हो। हाल के दिनों में, पुलिस फ़ोर्स की इमेज खराब हुई है। पुलिस वालों के पावर का गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से पेश आने के मामले पब्लिक डोमेन में हैं और चिंता की बात हैं। पुलिस फ़ोर्स की इज़्ज़त को धक्का लगा है। ऐसे में, हम दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए स्क्रीनिंग कमेटी जैसे सिस्टम की अहमियत और असर को कम नहीं करना चाहेंगे, ताकि यह पक्का हो सके कि ऐसे लोग पुलिस फ़ोर्स में न आएं जो इसकी क्रेडिबिलिटी कम कर सकते हैं। साथ ही, स्क्रीनिंग कमेटी को उस पर दिखाए गए भरोसे की अहमियत का एहसास होना चाहिए और सभी कैंडिडेट्स के साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए।

36. स्क्रीनिंग कमेटी की कार्रवाई को मनमाना, बिना किसी गाइडेंस और बिना रोक-टोक के बताया गया है। लेकिन, मौजूदा मामलों में, हमें इसका कोई सबूत नहीं दिखता। हालांकि, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कथित तौर पर गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी ने अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया है। यह अच्छी तरह से तय है कि ऐसे मामलों में भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में दिया गया बराबरी का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत नेगेटिव बराबरी की बात नहीं करता (फुलजीत कौर [फुलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य, (2010) 11 एस.सी.सी. 455])। इसका मकसद गैर-कानूनी काम या धोखाधड़ी को बढ़ावा देना नहीं है क्योंकि यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को दिखाता है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी, जो इस पूरी पॉलिसी के मकसद को पूरा करने के लिए बनाई गई है कि शक वाले बैकग्राउंड वाले लोग पुलिस फोर्स में न आएं, पॉलिसी से भटकती है, छूट देती है और अनचाहे लोगों को आने देती है, तो यह बेशक पुलिस फोर्स के साथ बहुत बुरा काम करने की दोषी है, लेकिन हम ऐसे मामलों का सहारा लेकर इस गैर-कानूनी काम को जारी नहीं रहने दे सकते। यह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का काम है कि वे जांच करें कि क्या स्क्रीनिंग कमेटी ने किसी भी मामले में पुलिस फोर्स के हितों से समझौता किया है और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो सुधार के लिए कार्रवाई करें। जनता के हित के लिए इस आरोप की सबसे ऊंचे लेवल पर गहराई से जांच की जरूरत है। शायद, पॉलिसी से ऐसे भटकाव ही पुलिस की ज्यादतियों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस मामले की जांच करेंगे और अगर आरोपों में दम है तो तुरंत जरूरी कदम उठाएंगे ताकि स्टैंडिंग आदेश में शामिल पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जा सके।

11. "ऑनरेबल एक्विटटल" शब्द दूसरे मामलों में भी सामने आया था, जैसे **मैनेजमेंट ऑफ़ रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली बनाम भोपाल सिंह पंचाल**[3]; और **आर.पी. कपूर बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य**[4] जिसमें यह माना गया था कि सिर्फ़ बरी होने से कोई कर्मचारी नौकरी में वापस आने का हक़दार नहीं बन जाता। यह माना गया कि बरी होना ऑनरेबल होना चाहिए। इसलिए, "ऑनरेबल एक्विटटल", "दोष से बरी", "पूरी तरह से बरी" जैसे शब्द आपराधिक प्रोसीजर कोड या पीनल कोड में नहीं हैं, और यह ठीक से बताना मुश्किल है कि "ऑनरेबल एक्विटटल" शब्दों का क्या मतलब है।

12. प्रदीप कुमार के केस (ऊपर) में भी यह बात दोहराई गई थी कि अगर किसी व्यक्ति को बरी या डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो यह साफ़ तौर पर नहीं माना जा सकता कि वह झूठे केस में फंसा था, या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसमें कही गई सटीक बातें नीचे दी गई हैं:

> **10.** किसी आपराधिक केस में बरी होना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए सही है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति को बरी या डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो हमेशा यह नहीं माना जा सकता कि वह गलत तरीके से फंसा था या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। जब तक यह इज्ज़त से बरी न हो, कैंडिडेट केस का फायदा नहीं उठा सकता। इज्ज़त से बरी होना क्या होता है, इस पर इस कोर्ट ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस बनाम एस. समुथिरम [इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस बनाम एस. समुथिरम, (2013) 1 एस.सी.सी. 598 : (2013) 1 एस.सी.सी. (क्रि) 566 : (2013) 1 एस.सी.सी. (एल&एस) 229] में विचार किया था, जिसमें इस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था: (एस.सी.सी. पेज 609, पैरा 24)
>
> **24.** इस कोर्ट के सामने आर.बी.आई बनाम भोपाल सिंह पांचाल [RBI बनाम भोपाल सिंह पांचाल, (1994) 1 एस.सी.सी. 541 : 1994 एस.सी.सी. (एल&एस) 594] में "ऑनरेबल एक्विटटल" शब्द का मतलब विचार के लिए आया था। उस मामले में, इस कोर्ट ने आपराधिक कोर्ट द्वारा ऑनरेबल एक्विटटल से निपटने वाले रेगुलेशन 46(4) के डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्स पर पड़ने वाले असर पर विचार किया है। उस संदर्भ में, इस कोर्ट ने माना कि सिर्फ़ बरी होने से कोई कर्मचारी सर्विस में वापस आने का हकदार नहीं हो जाता, यह माना गया कि बरी होना ऑनरेबल होना चाहिए। "ऑनरेबल एक्विटटल", "दोष से बरी", "पूरी तरह से बरी" जैसे शब्द आपराधिक प्रोसीजर कोड या पीनल कोड में नहीं हैं, जो न्यायिक फैसलों से बने हैं। यह ठीक से बताना मुश्किल है कि "ऑनरेबली एक्विटटल" शब्द का क्या मतलब है। जब आरोपी बरी हो जाता है।

[3] (1994) 1 एस.सी.सी 541

[4] ए.आई.आर 1964 एस.सी 787

प्रॉसिक्यूशन के सबूतों पर पूरी तरह विचार करने के बाद और यह देखते हुए कि प्रॉसिक्यूशन आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा है, यह कहा जा सकता है कि आरोपी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया।"

11. .....

12. .....

13. इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी आपराधिक मामले में बरी होने से वह स्वतः ही उस पद पर नियुक्ति के लिए हकदार नहीं हो जाता। फिर भी, नियोक्ता के लिए यह खुला है कि वह पूर्ववृत्त पर विचार करे और जांच करे कि क्या वह पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। मेहर सिंह [पुलिस आयुक्त बनाम मेहर सिंह, (2013) 7 एस.सी.सी 685: (2013) 3 एस.सी.सी (क्रि) 669: (2013) 2 एस.सी.सी (एल एंड एस) 910] और परवेज़ खान [मध्य प्रदेश राज्य बनाम परवेज़ खान, (2015) 2 एस.सी.सी 591: (2015) 1 एस.सी.सी (एल एंड एस) 544] मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि पुलिस सेवा में भर्ती होने वाले उम्मीदवार का चरित्र और अखंडता बेदाग होनी चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा। अगर वह बरी भी हो जाता है या उसे बरी कर दिया जाता है, तो भी यह नहीं माना जा सकता कि उसे इज्ज़त से बरी किया गया/पूरी तरह से बरी कर दिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला आखिरी माना जाना चाहिए, जब तक कि यह गलत इरादे से लिया गया न लगे। स्क्रीनिंग कमेटी को उस पर दिखाए गए भरोसे की अहमियत का भी ध्यान रखना चाहिए और कैंडिडेट की पूरी ईमानदारी से जांच करनी चाहिए।"

13. उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक केस, गिरफ्तारी या आपराधिक केस के पेंडिंग होने से जुड़ी ज़रूरी जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने के मामले में, इस कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य5 मामले में सही गाइडलाइंस तय की हैं। इसका पैरा 38.5 इस तरह है।

"38.5. ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने खत्म हुए आपराधिक केस के बारे में सच-सच बताया है, एम्प्लॉयर के पास अभी भी पहले के रिकॉर्ड पर विचार करने का अधिकार है, और उसे कैंडिडेट को अपॉइंट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।"

14. ऊपर दिए गए सभी मामलों में, पुलिस फोर्स में ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की ज़रूरत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। हाई कोर्ट ने इस फैसले में शामिल मुद्दों के हर

पहलू पर विस्तार से बात की है, साथ ही सिंगल बेंच के इस आदेश को भी सही ठहराया है कि डायरेक्टर जनरल, पुलिस पदानुक्रम में सबसे ऊंचे पद पर होने के नाते, याचिकाकर्ता के पुलिस फोर्स में शामिल होने के काबिलियत पर विचार करने के लिए सबसे सही जज हैं। यह आदेश सही और न्यायसंगत होने के कारण, हम भारत के संविधान के आर्टिकल 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इसमें दखल नहीं देना चाहते हैं।

15. कानून की यह अच्छी तरह से तय स्थिति है कि हालांकि भारत के संविधान के आर्टिकल 136 का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन इसके तहत दी गई शक्ति एक बहुत ही खास और असाधारण शक्ति है, इसका इस्तेमाल बहुत कम और खास मामलों में ही किया जाना चाहिए। चूंकि, हमें हाई कोर्ट के दिए गए आदेश में कोई कमी या गैर-कानूनी बात नहीं मिली, इसलिए यह याचिका खारिज करने लायक है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

एस.एल.पी खारिज।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।